सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 265 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 08 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को देंगे नई गति : सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी होने पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास तथा सदस्य पद पर देवशरण सेन, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में डॉ. श्रीमती ममता साहू तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान, उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे एवं सदस्य के रूप में सौरभसिंह जागृत, दुर्गा महेश्वर तथा दयावंत धर बांधे की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आनंद निषाद तथा सदस्य पद पर नेतराम निषाद, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डल रायपुर के अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार राजपूत तथा सदस्य पद पर श्रीमती सुमन मुथा एवं शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र नायक तथा सदस्य के रूप में श्री बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल, संतोष पटेल और प्रेम पटेल की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य पद पर श्री मनमथ नाथ शर्मा तथा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के सदस्य पद पर श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी की नियुक्ति की गई है। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज) तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर को दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और विश्व मंच पर सशक्त होती उसकी भूमिका का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी कूटनीति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है तथा मित्र देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

कमल विहार एवं रावभाटा सहित लगभग 121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां पोर्टल पर उपलब्ध

आरडीए की संपत्तियों की बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन

● घर बैठे करें आवेदन, बुकिंग और मेंटेनेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) ने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक नागरिक बिना कार्यालय आए घर बैठे ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन एवं बुकिंग कर सकेंगे।

प्राधिकरण ने प्रथम चरण में लगभग 121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें कमल विहार तथा रावभाटा सहित प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं की संपत्तियां शामिल हैं। कमल विहार में आवासीय फ्लैट, आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं, जबकि रावभाटा में व्यावसायिक संपत्तियां बुकिंग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुरूप आवास उपलब्ध कराया जा सके।

ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ अब हितग्राही घर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से मेंटेनेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। इससे नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और सेवाएं अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध तथा पारदर्शी बनेंगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदे साहू ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक, पारदर्शी एवं जनहितैषी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से समय की बचत होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी तथा संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी। डिजिटल भुगतान की सुविधा से हितग्राहियों को त्वरित एवं बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने नागरिकों से इस ऑनलाइन व्यवस्था का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

सेवाओं का डिजिटलीकरण कर नागरिकों को सहज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण कदम

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने बताया कि लंबे समय से संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया बंद थी। अब उपलब्ध सभी संपत्तियों को एक साथ ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है, जिससे नागरिक पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक तरीके से संपत्तियों की बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य अधिकाधिक सेवाओं का डिजिटलीकरण कर नागरिकों को सहज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

रायपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने के साथ-साथ नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन आवेदन, बुकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा से संपत्तियों के आवेदन, भुगतान एवं आवंटन की पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।

मौसम ने ली करवटः छत्तीसगढ़ में बारिश पर फिलहाल विराम, कई जिलों में हल्की बारिश के आसार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश में लगातार कई दिनों तक झमाझम बारिश के बाद मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। आज बुधवार से प्रदेश में बारिश की तीव्रता कम रहेगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राजधानी रायपुर में भी दो दिनों बाद धूप निकलने से लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली है।

हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने एक-दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं मानसूनी द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, जबकि एक अन्य चक्रवाती प्रणाली अरब सागर से लेकर बांग्लादेश तक सक्रिय है। इन मौसम प्रणालियों के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन व्यापक और भारी वर्षा की संभावना फिलहाल कम हो गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई, जबकि रायपुर में केवल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इस दौरान दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव और पेंड्रा रोड सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

राजधानी रायपुर में बुधवार को दिनभर बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है। शहर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

एक गड्ढा निगल गया खेतः राजनांदगांव में अचानक जमीन धंसी, अधिकारियों ने सील किया क्षेत्र; ग्रामीणों में दहशत

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के कबीर मठ नदिया गांव में एक किसान के खेत में रहस्यमयी तरीके से जमीन धंस गई। लगातार बारिश के बाद हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल है। किसान अमर सिंह रावटे के खेत में अचानक जमीन धंसने लगी।

देखते ही देखते एक छोटा सा गड्ढा विशाल धंसाव में बदल गया। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आसपास के गांवों से भी लोग इस अनोखे धंसाव को देखने पहुंच रहे हैं।

मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व टीम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी और राजस्व निरीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। एडीएम सी.एल. मार्कण्डेय ने बताया कि राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को घेर दिया गया है।

जियोलॉजिकल जांच की मांग

प्रथम दृष्टया यह कुएं जैसी संरचना प्रतीत हो रही है। वास्तविक कारणों की पुष्टि जियोलॉजिकल विभाग की जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन अब जियोलॉजिकल विभाग की टीम बुलाकर पूरी जांच कराएगा। फिलहाल धंसाव वाले स्थान पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर कौतूहल चरम पर है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और जांच पूरी होने तक संदिग्ध जगह से दूर रहने की अपील की है।

संपादकीय

शर्मसार हैं हम

बारह साल की बच्ची पर हैवानियत का कहर

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूलें हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक रिक्शेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता है।

" राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है।

निस्संदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्वेलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफआक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? हवस के भूखे भेड़िए न उम्र देखते हैं, न किसी बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिश्तों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। हवस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए। घर वालों से चोरी-छिपे अनजान लोगों पर यकीन करने की वजह से अकसर बेटियां अपराधियों की आसान शिकार बनती हैं। यौन अपराधों के उफान के दौर में पुलिस और स्त्री रक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी नये दौर की नई चुनौतियों के मुताबिक तैयार करना होगा। इसमें चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं की सजगता -सक्रियता बढ़ाने तथा पॉक्सो व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सख्त बनाने की जरूरत है। अभिभावक व स्कूल-कालेज बच्चियों को यौन-हिंसा से बचने और आत्मरक्षा से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा करें। यदि इस दिशा में गंभीर पहल नहीं हुई तो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर लगाए जा रहे 'रेप कैपिटल' के आरोप हकीकत समझे जाने लगेंगे।

मूल्य श्रृंखला का जुड़ाव: पीएम मित्र पार्क के ज़रिए कैसे भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की बदल रही है तस्वीर

पबित्रा मार्गेरिटा

सदियों से, भारत की पहचान उसके परिधानों से गहराई से जुड़ी रही है। चाहे वह कश्मीर के पश्मीना की लंबे समय तक रहने वाली गर्माहट हो, असम के मूंगा सिल्क की सुनहरी चमक हो, तमिलनाडु की शाही कांजीवरम साड़ियाँ हों, चंदेरी की बुनाई हो या सूरत के कारीगरों की कपड़ों पर मशहूर कारीगरी। आज भी यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, जो जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। खेती के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला यह क्षेत्र 45 मिलियन लोगों को सीधे तौर पर और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देता है। इससे ग्रामीण समुदायों को मजबूती मिलती है और देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का रास्ता खुलता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के एक साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के उलट, भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग जगहों पर फैले हुए मॉडल के तौर पर विकसित हुई। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, कपड़े सिलने और निर्यात जैसी गतिविधियाँ अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, जिसका अर्थ था कि एक कपड़ा बनने के दौरान अक्सर कई राज्यों की सीमाओं से गुज़रता था। इस बिखराव के कारण कई संरचनात्मक बाधाएँ पैदा हुईं। इसने बड़े पैमाने पर काम करने, आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और आखिरकार मज़दूरों की उत्पादकता को सीमित कर दिया।

इसके साथ ही, मल्टी-मॉडल संपर्क में कमियों की वजह से लॉजिस्टिक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रोडक्शन के अलग-अलग चरणों के बीच हर बार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या संभालने में अतिरिक्त खर्च और ढुलाई का किराया लगता है। कई चरणों में लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से कुल लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और सामान को तेज़ी से बाज़ार तक पहुँचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो आज की रिटेल व्यवस्था में बार-बार ऑर्डर देने वाले साइकल में एक बहुत बड़ी और नुकसानदायक कमी है।

वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की ज़रुरत है। दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 8% से 10% और औद्योगिक जल प्रदूषण में 20% है। हज़ारों छोटी-छोटी और अलग-अलग जगहों पर फैली इकाइयों में नियमों को लागू करना और सही तरीके से प्रबंधन करना पहले एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती रहा है।

इन रुकावटों को व्यवस्थित रूप से दूर करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना शुरू की, जिसके लिए 4,445 करोड़ का बजट रखा गया। यह एक अहम कदम था, जो एक ऐसा व्यापक मॉडल पेश करता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों से जुड़े लोगों और निजी साझेदारों के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाती है।

इस योजना के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी '5एफ' फॉर्मूला है यानी फार्म (खेत) से फाइबर (रेशा) से फैक्टरी (कारखाना) से फैशन और फारेन (विदेश) तक पहुंच। यह सोच सीधे तौर पर उस बात को सामने लाती है, जो भारत को वैश्विक मंच पर अलग बनाती है: हमारी संपूर्ण और बेहद विविध मूल्य श्रृंखला। कच्चे माल के आयात या सिर्फ तैयार कपड़ों की बनावट पर निर्भर रहने वाले दूसरे देशों के उलट, भारत वस्त्रों को बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें किसानों के खेतों से लेकर हाई-फैशन रनवे तक की प्रक्रिया शामिल है। इस अनोखी समझ की वजह से, हमारी विकास रणनीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से सामाजिक समानता के बीच एक खास संतुलन बनाने की ज़रुरत है। विस्तार करते समय, हमें हर क्षेत्र के कल्याण का ध्यान रखना होगा, ताकि साधारण किसान और ग्रामीण बुनकर से लेकर कपड़े के निर्यातक तक, कोई भी पीछे न छूटे। पीएम मित्र फ़्रेमवर्क इसी संतुलन को हासिल करता है।

इन पार्कों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे ज़रूरी बात यह है कि इस नज़दीकी से शुरुआत से आखिर तक ट्रैकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य कस्टडी चेन देते हैं। इससे कड़े वैश्विक ईएसजी नियमों का पालन होता है और विदेशों में प्रीमियम कीमत पाने का रास्ता भी बनता है।

1,000 एकड़ से ज़्यादा के एक ही इलाके में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग और कपड़ा बनाने की सुविधाओं को एक साथ लाने से अलग-अलग राज्यों के बीच सामान ले जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इससे माल ढुलाई का खर्च और ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है और सामान तेज़ी से बाज़ार तक पहुँच पाता है। समर्पित माल गलियारे और एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण, विदेशी बाज़ारों तक सामान पहुँचाना बहुत सस्ता और किफायती हो जाता है। हर पार्क में 'प्लग-एंड-प्ले' इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें बिजली के खास सब-स्टेशन, लगातार पानी की सप्लाई और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार फैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ज़ेडएलडी) तकनीक वाले उन्नत एडवांस्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और आधुनिक सुविधाएँ भी होती हैं, जिससे कारोबारियों पर ढ़ांचागत बोझ कम पड़ता है और कारोबार करने में आसानी होती है।

पीएम मित्र पार्क तेज़ी से कागज़ी योजनाओं को असल ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं। इस योजना में सात रणनीतिक पार्क शामिल हैं: पाँच ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट विरुधुनगर (तमिलनाडु), नवसारी (गुजरात), कलबुर्गी (कर्नाटक), धार (मध्य प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और दो ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट वारंगल (तेलंगाना) और अमरावती (महाराष्ट्र) में। अब तक, इस योजना में कुल 69,899 करोड़ के निवेश की दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसमें से ?27,658 करोड़ का निवेश पहले ही हो चुका है।

10 मई, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वारंगल में पहले कार्यरत पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में पहले ही 3,862 करोड़ का निवेश हो चुका है और यहाँ विश्व-स्तरीय पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढ़ांचे पर काम किया जा रहा है। ये विशेषताएँ स्थायित्व के उन मानकों को दर्शाती हैं, जिन्हें सभी सात पार्क साइटों पर स्थापित किया जा रहा है।

पूरे देश में एक साथ काम शुरू होने से सहकारी संघवाद की तेज़ी और सफलता दोनों साफ दिखती है, जहां सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 100% ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और पर्यावरण से जुड़ी मंज़ूरी भी मिल गई है। पाँच ग्रीनफील्ड साइट्स के लिए जेवी एग्रीमेंट और एसपीवी पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। 2,158 एकड़ में फैले सबसे बड़े पार्क, धार (मध्य प्रदेश) में ?21,436.9 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई गई है। इसी तरह गुजरात (13,084 करोड़), महाराष्ट्र (12,925 करोड़), तमिलनाडु (6,600 करोड़), उत्तर प्रदेश (5,345.8 करोड़) और कर्नाटक (1,700 करोड़) में भी काम को लेकर तेज़ी देखी गई है। तेज़ी से हो रहे इस काम के पीछे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का सक्रिय नेतृत्व है। उनके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय अपने कामकाज के तरीकों में तेज़ी लाया है, मंत्रालय ने प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया है और राज्य सरकारों के साथ अभूतपूर्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है।

लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली पैमाना इसके मानवीय प्रभाव में दिखता है। प्रत्येक पार्क को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यानी सभी सात स्थलों को मिलाकर, 21 लाख से अधिक औपचारिक आजीविकाएं हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को अहम सामाजिक-आर्थिक नींव प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक रूप से परिधान निर्माण उद्योग की रीढ़ हैं।

यह व्यापक ढ़ांचागत प्रयास वस्त्र क्षेत्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण 2030 के लिए एक अहम लॉन्चपैड का काम करता है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350 बिलियन डॉलर की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। ऐतिहासिक विखंडन को विश्व स्तरीय, एकीकृत पैमाने से बदलकर करके, पीएम मित्र एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। सशक्त नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हम भारत को वस्त्रों के निर्विवाद, टिकाऊ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)

बिजनेस मॉडल बदलने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है

एन. रघुरामन

ग्रामीण भारत की वे कालजयी तस्वीरें याद कीजिए। बच्चे नंगे पैर कीचड़ भरी सड़कों पर नाच रहे हैं। पानी से भरे गड्ढों में छप-छप कर रहे हैं। पहली बारिश में भीगते हुए दोनों बांहें फैलाकर शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज बना रहे हैं। शहरी लोगों को यह बारिश का गर्मजोशी भरा जश्न लगता है। लेकिन उन बच्चों के लिए यह खेल से कहीं ज्यादा है।

वे जानते हैं कि बारिश की हर बूंद का मतलब है जीवन- पारिवारिक खेतों के लिए पानी, मवेशियों के लिए चारा, थाली का भोजन और भविष्य की उम्मीद। लेकिन इस बार मानसून में ऐसे दृश्यों का टोटा है। अल-नीनो के कारण अनियमित और देरी से हुई बारिश ने खेती की लय ही नहीं बिगाड़ी, बल्कि इन मासूम खुशियों को भी छीन लिया। आमतौर पर बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने वाली गांवों की सड़कें अधिक समय तक धूल से भरी रहीं। जब मानसून ठहर जाता है तो सिर्फ फसलें ही नहीं, पूरा ग्रामीण बचपन भी उसका इंतजार करता है।

इसीलिए महाराष्ट्र के जालना जिले में चल रहे एक प्रयोग पर पूरे देश का ध्यान जाना चाहिए। करीब 16 लाख एकड़ कृषि भूमि में फैला यह जिला खेती की सोच में उल्लेखनीय बदलाव की कोशिश कर रहा है। हजारों किसान एक जैसी फसल बोएं और एक जैसा ही जोखिम उठाएं, इसके बजाय जालना की जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल एक अभियान शुरू कर 778 ग्राम पंचायतों के 970 गांवों से अपील कर रही हैं कि वे हर गांव में कम से कम 20 एकड़ जमीन कम पानी में होने वाली और अधिक कीमत की फसलों के लिए अलग रखें। इनमें चिया सीड्स, शहतूत, अलसी, सफेद मूसली, शतावरी और रेशम उत्पादन जैसी फसलें शामिल हैं। यह फसलों में योजनाबद्ध विविधीकरण की कोशिश है। ऐसे दौर में, जब जलवायु-अनिश्चितता न्यू नॉर्मल बन गई है तो अप्रत्याशित मानसून की चुनौती के खिलाफ यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण जमीनी पहलों में से एक बन सकती है।

सिर्फ जालना ही नहीं, पंजाब भी दशकों से एक सीख देता रहा है। भूजल स्तर में गिरावट के बावजूद वहां कृषि में धान की खेती का दबदबा रहा है। लेकिन आज कई प्रगतिशील किसान जमीन के एक हिस्से में मक्का, सब्जियां और फलों के बाग लगा रहे हैं। सिक्किम अलग सोच का सबसे मजबूत उदाहरण पेश करता है। वहां के किसानों ने पूरे राज्य में जैविक खेती अपनाकर उत्पादन की मात्रा के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाई है। इस बदलाव में धैर्य लगा, लेकिन आज राज्य की एक खास पहचान है, जो अधिक कीमत चुकाने वाले ग्राहकों को आकर्षित करती है।

ओडिशा के आदिवासी जिले बिल्कुल अलग मॉडल प्रदर्शित करते हैं। हल्दी, अदरक और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों ने किसान उत्पादक संगठनों के जरिए पारिवारिक आय में उल्लेखनीय सुधार किया है। ये संगठन उपज एकत्र करते हैं, क्वालिटी बेहतर बनाते हैं और अच्छे दामों के लिए मोलभाव करते हैं। कम बारिश और अत्यधिक तापमान वाले गुजरात के कच्छ में किसानों ने ड्रिप सिंचाई से बंजर जमीन को अनार, खजूर और ड्रैगन फ्रूट के लाभकारी बागानों में बदल दिया है। कभी नामुमकिन लगने वाली चीज आज फलती-फूलती बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जालना का '20 एकड़ मॉडल' इसीलिए इतना प्रभावशाली है, क्योंकि यह किसानों से जमीन के सिर्फ छोटे-से हिस्से पर प्रयोग करने को कहता है। पांच एकड़ जमीन वाले किसान को पूरा खेत दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। विस्तार करने से पहले वह नई फसल को महज आधा एकड़ जमीन देकर भी आय, लागत और जोखिम की तुलना कर सकता है।

इन सभी उदाहरणों में एक समान सबक है। इन सभी ने अपनी जमीन को क्लाइमेट अडॉप्शन की जीती-जागती प्रयोगशाला में बदल दिया। सफलता हमेशा अधिक जमीन पर खेती से नहीं मिलती। अकसर यह इस बात से मिलती है कि जमीन से समझदारी भरी पैदावार कैसे ली जाए। इस साल जून में सामान्य से कम बारिश और कमजोर मानसून ने पहले ही यह चिंता बढ़ा दी है कि वर्षा आधारित किसान फिर-से पैदावार का नुकसान झेल सकते हैं। ऐसे में फसलों की विविधता और जलवायु-अनुकूल खेती पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है।

पारिवारिक त्याग की अनदेखी कर आज़ादी की चाह

क्षमा शर्मा

हाल ही में कुछ युवाओं की दुखद मौतों के बाद स्त्री आजादी को लेकर नकारात्मक नैरेटिव सामने आये। वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्त्री-अधिकारों के नाम पर जश्न मनाते नजर आए। यह संवेदनहीनता की अति ही है लैंगिक, जाति या फिर विचारधारा के नाम पर किसी की मृत्यु पर खुशी जताना। पश्चिम के मापदंड अपनी जगह हैं, पर भारतीय सामाजिक ढांचे में इस प्रवृत्ति का औचित्य क्या है?

फरीदाबाद में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने वीडियो बनाया और कहा कि वह घर के सारे काम करता है, व्यापार भी करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे मारती-पीटती है। दूसरा किस्सा पुणे के केतन का है, कहा गया कि उसकी मंगेतर सिया ने अपने मित्र चेतन की मदद से उसे लोहागढ़ पहाड़ी से धक्का दे दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह हकलाता भी था। इन दोनों मामलों में युवाओं ने जान गंवाई। इनके घर वालों, परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं।

मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा-हा-हा करते वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी।

जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो उनका अर्थ हमारे दैनंदिन जीवन की सुविधाओं से जुड़ा होता है। छोटे, बड़े की भावना को खत्म करने की बात होती है। लेकिन मृत्यु पर हंसना, मीम्स बनाना, कहना कि वक्त आ गया है कि अब स्त्रियों को अपने प्रति किए गए हर अपराध का बदला लेना चाहिए, कितना दुखद है। अंग्रेजी की एक बड़ी लेखिका और एक बड़े लेखक ने तो यह तक कहा कि सिया ने केतन को मारा, इसके लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। वे न अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात लौट सकती हैं, न शराब पी सकती हैं। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं। जिनके इर्द-गिर्द सेवकों और सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज है, लेकिन ज्ञान वे उन आम लड़कियों को दे रहे हैं, जो अमूमन अपराध की जद में होती हैं। 'अपनी सुरक्षा अपने हाथ' वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। फिर देर रात तक पार्टी करना या शराब पीना आम लड़कियों का जीवन नहीं है। और क्या स्त्रियों के लिए शराब पीना इतनी अच्छी बात है। फिर ऐसा क्यों है कि अक्सर महिलाएं अपने घर के आसपास शराब के ठेके खुलने का विरोध करती हैं। शराबबंदी की मांग करती हैं क्योंकि शराब के कारण ही उनके पति तरह-तरह की हिंसा करते हैं। यदि वे पैसे भी कमाएं, तो उनके पैसे शराब पीने के लिए छीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है।

गांधी जी जिन्होंने कहा था कि शराब आत्मा का नाश करती है, उनकी इस शिक्षा को भी लोग भूल गए हैं। डाक्टरों की सलाह भी याद नहीं रखते, जो कहते हैं कि शराब पीने से शरीर के तमाम अंगों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि इन लोगों की मानें तो देश में चलने वाले जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए।

लेकिन 'माई लाइफ और माई च्वाइस' का विचार एलीट स्त्री-पुरुषों के मन में इतना बसा हुआ है कि वे अपनी शर्तों को दूसरों पर लाद रहे हैं और इन्हें ही दूसरों की च्वाइस बता रहे हैं। वे सिया का बचाव करते हुए उसके घर वालों और हर एक के घर वालों को दोष दे रहे हैं। पश्चिम का उदाहरण बार-बार दिया जा रहा है कि वहां देखो स्त्रियों को कितनी आजादी है। क्या सचमुच!

अपने यहां माता-पिता बच्चों को हमेशा बच्चा मानते हुए, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाते हैं। पढ़ने के लिए विदेश भेजते है। करोड़ों रुपये का लोन लेते हैं, उसे खुद चुकाते हैं। बच्चों के लिए घर बनाते हैं। यानि कि अपनी उम्र और सारे संसाधन वे बच्चों के लिए लगा देते हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। माता-पिता के सारे संसाधन चाहिए, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर जीना है। कौन रोकता है, लेकिन फिर संसाधन भी खुद जुटाइए। माता-पिता की जमीन-जायदाद में भी हिस्सा मत मांगिए। बीमारी-हारी में भी अपनी मदद खुद कीजिए। ड्रीम वैडिंग करना हो, तो खुद पैसे जुटाइए। उनके सम्पर्कों का भी लाभ मत उठाइए।

अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हां मन की बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं।

विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं चुकाते। विदेशों में कई ऐसे आदमियों से मिली, जिनकी उम्र पचास के पार है, लेकिन अभी तक वे अपनी पढ़ाई के लिए उठाए गए कर्ज को चुका रहे हैं। भारत में तो माता-पिता की हालत ये है कि ताउम्र खटते भी हैं और पिटते भी हैं। बातें बनाते रहिए कि बुजुर्गों के लिए क्या-क्या होना चाहिए।

विमर्शों की नकारात्मकता कितनी है कि जहां मौत का भी जश्न मनाया जाए। जाति, धर्म, लिंग देखकर शोक और खुशी प्रकट की जाए, इससे यही पता चलता है कि हमारा वैचारिक आधार कितना पोला है, जहां हम किसी मरने वाले की जाति या जेंडर देख रहे हैं। जब एक मशहूर इनफ्लुएंसर ने कहा कि यह अकेला क्यों मर गया, इसके बीवी -बच्चे क्यों नहीं मर गए। यह एक तरह से वही हिटलरी विचार है, जिसकी आलोचना करते-करते ऐसे लोग दुबले हुए जाते हैं। कोई सवर्ण, कोई दलित, कोई स्त्री, कोई पुरुष, किसी की भी मृत्यु हंसने और आनंद मनाने के लिए कैसे हो सकती है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से एक नफरती विचारों की होड़ लगी है। सोचते तो ये थे कि तकनीक बढ़ेगी, तो तमाम तरह के नफरत फैलाने वाले विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलटा है। नफरत और बदले की भावना की फसल लहलहा रही है। लोग भूल रहे हैं कि नफरत से नफरत उपजती है और बदले से बदला।

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

किंडरगार्टन की वार्षिक प्रतियोगिता जैसी कूटनीति

यूरोप में गर्मी विकट हो गई है। जर्मनी से गमछे की मांग आने वाली है और स्विट्ज़रलैंड में सत्तू से गर्मी निपटाई जाएगी। धुरंधर श्री जब स्विट्ज़रलैंड में बनने जाएगी। लोहागढ़ किले के मंगेतर हत्याकांड में वह उज्ज्वल निकम सरकारी वकील बने हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकी कसाब को फांसी दिलवाई थी।

पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने खंडन किया है कि लोहागढ़ किला कांड में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। दुनियाभर में जहां भी हत्याकांड, आतंककांड या बमबाजी हो, पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है कि हमने नहीं किया। हालांकि, पाकिस्तानी आतंकियों को यह जानकर बुरा लगता है कि उनके होते हुए हत्या और आतंक का कोई दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे चल गया।

पाक पीएम ने पाक आर्मी जनरल से कहा, 'सर, अमेरिका और ईरान में जैसी और जितनी होनी थी, शांति हो गई। आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। अब हुक्म दें तो अपने ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान और कश्मीर में भी शांति करवा लें।' सर ने बताया, 'यह अपने बस की बात नहीं है। हमारी शांति एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर मिलती है, लोकल नहीं। घरेलू शांति का विभाग अभी स्टार्टअप मोड में है और उसमें निवेशक नहीं मिल रहे हैं।'

यूरोप में गर्मी विकट हो गई है। जर्मनी से गमछे की मांग आने वाली है और स्विट्ज़रलैंड में सत्तू से गर्मी निपटाई जाएगी। धुरंधर श्री जब स्विट्ज़रलैंड में बनने जाएगी तो वहां बर्फ के पहाड़ की जगह रेत और ऊंटों का रेला तो झेल लेंगे, पर हाय, यह कैसे देखा जाएगा कि सिलसिला फिल्म के रीमेक में नीदरलैंड के ट्यूलिप फूलों की जगह रेत का बैकग्राउंड होगा। कुंभकर्ण ने ट्रंप से कहा, 'भाई, मेरी तरह बन जा। महीनों सिर्फ सो, दुनिया शांत हो जाएगी।

रात में सोता क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता है। किसी दिन मजे-मजे में एटम बम नहीं चला देना।' खैर, कुंभकर्ण सोता था तो लंका खतरे में पड़ती थी। ट्रंप जागते हैं तो दुनिया खतरे में आ जाती है। शेयर बाजार कांपने लगते हैं, तेल के दाम उछलने लगते हैं। मुझे फिर डर है कि ट्रंप यह न कह दें, 'पूरी दुनिया मेरी है। पूरी दुनिया को फुटबॉल बना दूंगा। कनाडा मेरा है। ग्रीनलैंड मेरा है। मेक्सिको मेरा है। और जो मेरा नहीं है, उसे टैरिफ लगाकर अपना करूंगा। सब मेरे नौकर हैं। मेरी मम्मी कहती हैं मैं बहुत जीनियस हूं।'

अब तो हालत यह है कि वैश्विक कूटनीति किसी किंडरगार्टन की वार्षिक प्रतियोगिता से ज्यादा लगने लगी है, जहां हर बच्चा कह रहा है, 'यह खिलौना मेरा है।'

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

जोन आयुक्त ने विकास कार्यों का लिया जायजा

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आज जोन 2 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया गया। जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे ने अधिकारियों की टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जोन आयुक्त ने जोन 2 के अंतर्गत बनाए जा रहे नए डॉग हाउस का बारीकी से अवलोकन किया, अविलंब प्रारम्भ करवाने हेतु चर्चा की गई। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसएलआरएम सेंटर में चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। कुरूद सुंदर विहार क्षेत्र के नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए नवनिर्मित नवीन सीसी रोड का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता को परखा गया।

बीएसपी क्षेत्र के भवनों का होगा नया माप-जोख

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने संपत्तिकर निर्धारण और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के आदेशानुसार बीएसपी क्षेत्र में निर्मित भवनों एवं भूमियों का व्यापक परिमाप (सर्वे) अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत सेक्टर-6 स्थित एम.जी.एम. स्कूल के पास सड़क एवेन्यू-ए में बने भवनों के माप-जोख से की गई। निगम की टीम प्रत्येक भवन का वास्तविक क्षेत्रफल, निर्माण की स्थिति एवं अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर संपत्तिकर निर्धारण के लिए आधार तैयार कर रही है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस सर्वे का उद्देश्य संपत्तिकर निर्धारण में पारदर्शिता लाना, वास्तविक निर्माण के अनुसार कर निर्धारण करना तथा राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। आने वाले दिनों में बीएसपी क्षेत्र के अन्य सेक्टरों में भी यह अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। सर्वे कार्य के दौरान निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रहलाद लहरे तथा राजस्व अमला गणित बघेल, टेकराम हरिन्द्रवार और प्रकाश महलवार मौजूद रहे। निगम की टीम ने मौके पर भवनों का माप लेकर आवश्यक अभिलेख तैयार किए।

बीएसपी में एडवांस्ड इंडस्ट्रियल हाइड्रॉलिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत संचालित एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के सहयोग से एडवांस्ड इंडस्ट्रियल हाइड्रॉलिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संयंत्र के अभियंताओं एवं अनुरक्षण कार्मिकों की तकनीकी दक्षता को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें आधुनिक औद्योगिक हाइड्रॉलिक प्रणालियों, अनुरक्षण तकनीकों एवं प्रभावी समस्या-निवारण पद्धतियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक औद्योगिक हाइड्रॉलिक प्रणालियों के संचालन, अनुरक्षण एवं समस्या-विश्लेषण से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा आधारित प्रशिक्षण के साथ-साथ हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। इससे उन्हें आधुनिक हाइड्रॉलिक अनुप्रयोगों की बेहतर समझ विकसित करने, समस्या-समाधान क्षमता बढ़ाने तथा उपकरणों की विश्वसनीयता एवं परिचालन दक्षता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में औद्योगिक सुरक्षा, व्यवस्थित अनुरक्षण प्रणाली तथा बदलती औद्योगिक तकनीकों को अपनाने के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों को सुरक्षित कार्य व्यवहार, निवारक अनुरक्षण तथा नवीनतम औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से नियमित रूप से तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अपने ज्ञानार्जन एवं विकास तंत्र को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

संभाग में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद बीज की कमी न हो- संभागायुक्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद बीज की कमी न होने पाएं यह सुनिश्चित किया जाए। संभाग अंतर्गत सभी जिलों में उपलब्ध खाद एवं बीज का वितरण किसानों को समय पर किया जाए। संभाग आयुक्त राठौर ने संभाग आयुक्त कार्यालय में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक कृषि से संभाग अंतर्गत खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए उक्त बातें कही।

संयुक्त संचालक कृषि ने अवगत कराया कि संभाग में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। उपलब्धता के आधार पर जिलों में कृषि विभाग के अमले द्वारा वितरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभाग के जिलों में लक्ष्य के मुताबिक यूरिया 92 प्रतिशत, डीएपी 40 प्रतिशत, एसएसपी 114 प्रतिशत, एमओपी 98 प्रतिशत एवं एनपीके 88 प्रतिशत उपलब्ध है। इसी प्रकार यूरिया 63 प्रतिशत, डीएपी 30 प्रतिशत, एसएसपी 74 प्रतिशत, एमओपी 63 प्रतिशत एवं एनपीके 66 प्रतिशत सहकारी एवं निजी भंडारण के माध्यम से किसानों को वितरित की जा चुकी है। संभाग अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला एवं कबीरधाम जिला अंतर्गत भण्डारित 101926 बॉटल नैनो यूरिया में से 61736 बॉटल नैनो यूरिया वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार 83477 भण्डारित नैनो डीएपी में से 48322 बॉटल नैनो डीएपी का वितरण किसानों को हो चुका है। संभाग के जिलों में मांग के विरूद्ध 108597 क्वि. विभिन्न किस्म के खरीफ बीजों का भण्डारण किया गया है। जिसमें से 98069 क्वि. बीजा का वितरण किसानों को किया जा चुका है।

संभाग आयुक्त राठौर ने कृषक प्रशिक्षण पर जोर देते हुए निर्धारित कार्ययोजना के मुताबिक कृषकों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही चालू शिक्षा सत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष जोर देने तथा युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अब तक पद ग्रहण न करने वाले शिक्षकों पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया। संभाग आयुक्त ने नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता पर जोर देते हुए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम-रैली आदि आयोजित करने कहा। उन्होंने उक्त कार्यक्रमों में समाज के अन्य वर्ग को भी भागीदारी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों संबंधित शिकायत व जानकारी साझा करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई टोल फ्री नं. 1933 सभी स्कूल, कॉलेजों के प्रवेश द्वारों पर वॉल राइटिंग कराई जाए।

संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी द्वारा निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने तथा आरईएस द्वारा गांवों में महिला सदन का निर्माण गांव के अन्दर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) पदुमलाल यादव और उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर एवं समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री राम जन्मोत्सव समिति के चरोदा प्रखंड की नई कार्यकारिणी घोषित

भिलाई। श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में चरोदा प्रखंड की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रमेश माने जी एवं प्रदेश महामंत्री बुद्धन सिंह ठाकुर जी की अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष मदन सेन जी की सहमति एवं उपस्थिति में चरोदा प्रखंड की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई।

जिलाध्यक्ष मदन सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि नई कार्यकारिणी में वाई. नारायण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर पी. एन. शर्मा, सुशील यादव, के. वीरभद्र राव एवं सुब्रत दास को नियुक्त किया गया है। महामंत्री पद पर सत्य प्रकाश शर्मा एवं सुनील बैठा, मंत्री पद पर मनजीत लहरे, माला भट्ट, हरीश साहू एवं लेखराम यादव, तथा कोषाध्यक्ष पद पर रिंकु तिवारी को नियुक्त किया गया है।

इसी क्रम में आर. एस. श्रीनिवास को मीडिया प्रभारी, हितेश चन्द्र साहू को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी, देवमय मित्रा को कार्यालय प्रभारी तथा केदारेश्वरी (मीनाक्षी) को विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

कार्यकारिणी सदस्यों में बी. ए. नायडू, राकेश कुमार गजेन्द्र, बी. नागु (बाबा), उमाशंकर चक्रधारी, वीरू नायक, राजेश विश्वकर्मा, कमल तांडी, लोही दास, मलय बनर्जी, वासु शिखा, ए. कृष्णा, गणेश प्रसाद, दिनेश गढ़ेवाल, ए. वी. शंकर राव एवं हेमराज बाग को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला शाखा की अध्यक्ष के रूप में सुधा बर्मन की नियुक्ति की गई है।

भिलाई नगर प्रवासांध्र नाई ब्राह्मण समाज की नई कार्यकारिणी का गठन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। प्रवासांध्र नाई ब्राह्मण समाज, भिलाई नगर (जिला दुर्ग) के त्रिवार्षिक निर्वाचन वर्ष 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन समाज के संविधान एवं संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप संपन्न हुआ। इस दौरान समाज के सभी सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें समाज के विकास, संगठन की मजबूती और सामाजिक एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया गया।

निर्वाचन में एम. रामा राव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर रवि, सभापति एल. राजू, उपसभापति एन. कालिदास, महासचिव एस. सन्मुख राव,

कोषाध्यक्ष व्ही वेणु गोपाल राव, उपकोषाध्यक्ष एन राजेश्वर राव, सहसचिव पी. हरीश एवं ई. कोटेश्वर राव तथा संरक्षक के रूप में आर. अप्पा राव एवं के. सोमेश्वर राव को जिम्मेदारी सौंपी गई।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष एम. रामा राव ने अपने संबोधन में समाज के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती सभी के सहयोग और सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने समाज के प्रत्येक परिवार को एक सूत्र में बांधने, युवा पीढ़ी को समाज से जोड़ने, शिक्षा, संस्कार एवं सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने तथा समाज के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा, सहयोग और समन्वय ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन तथा जरूरतमंद परिवारों की सहायता जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और अंत में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समाज की एकता, प्रगति एवं सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पीएम आवास के संबंध में लिखा पत्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे, इसके लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नई दिल्ली में 28 एवं 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में श्री चौहान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

उपमुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई, जिसके दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आईं, जिसमें सर्वेक्षण के समय कुछ पात्र व्यक्ति पलायन अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो पाया और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका। साथ ही कुछ पात्र परिवारों का सर्वे तो हुआ, लेकिन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो सकी, जिससे ग्राम सभा में उनकी पात्रता प्रदर्शित नहीं हो पाई।

इन दोनों कारणों से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे पात्र परिवार आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ के हकदार हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय एवं पहल की जाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को आवास के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

आयुष्मान, ई-ऑफिस और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति में प्रतिदिन 7 घंटे की अवधि पूरी नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र के चयन में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति को आधार बनाने को कहा। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिवों एवं पटवारियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए संबंधित तहसीलदारों से आवश्यक लोकेशन उपलब्ध कराने को कहा।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सकों की रोस्टर ड्यूटी ई-ऑफिस के माध्यम से जारी करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जनप्रतिनिधियों को भी शासकीय ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव तथा पार्षदों को सरकारी ई-मेल आईडी प्रदान कर शासकीय फाइलों का डिजिटल माध्यम से त्वरित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों का आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन एवं ऑनबोर्डिंग कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने

आयुष्मान कार्ड अभियान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1300 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, जलजनित रोगों की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग एवं छिड़काव तथा सभी विभागों के लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेजरी अधिकारी को विभागवार बिजली बिल मद में उपलब्ध बजट की सूची तैयार करने को भी कहा। बैठक में पट्टाधारी सर्वे की प्रगति, शासकीय स्कूलों में बायोमेट्रिक अपडेट शिविर, निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के बाद विशेष शिविर आयोजित करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा खाद की उपलब्धता की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने विधानसभा प्रश्नों का समय-सीमा में प्राथमिकता के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन और पीजीएन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग का नहीं है तो फीडबैक में लिख दे की यह आवेदन इस विभाग से संबंधित नही है, ताकि आवेदक संबंधित विभाग में फिर से आवेदन कर सके। उन्होंने जनदर्शन में दो माह से लंबित 96 आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में ग्राम पंचायतों के नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों में तेजी लाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा नगरीय निकायों को जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान किया जा सके।

बैठक में वनमण्डाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस, एसडीएम हरवंश मिरी, एसडीएम सोनल डेविड, लवकेश ध्रुव, सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

स्वेच्छानुदान मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल, मांझीगुडा को 10 कंप्यूटर प्रदत्त

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने स्वेच्छानुदान मद से बस्तर जिले के विकासखंड दरभा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा चिंगपाल को 10 कंप्यूटर प्रदान किए। इसके लिए राज्यपाल द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई थी। लोक भवन में आज राज्यपाल ने विद्यालय के लिए कंप्यूटरों का औपचारिक रूप से हस्तांतरण किया। इन कंप्यूटरों के माध्यम से सुदूर वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल का विकास होगा। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, उप सचिव निधि साहू तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा (जिला बस्तर) के प्राचार्य उपस्थित थे।

ईवी गार्बेज रिक्शा और लोडर वाहन से बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण को नई गति देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए गए ईवी गार्बेज रिक्शा और ईवी लोडर वाहन बहुआयामी बदलाव के वाहक बन रहे हैं। इन वाहनों के माध्यम से जहां गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नियमित रोजगार और आय का नया अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ईंधन रहित संचालन के कारण ये वाहन पर्यावरण संरक्षण और संचालन लागत में कमी की दृष्टि से भी प्रभावी साबित हो रहे हैं। बालोद जिले के जनपद पंचायत डौंडीलोहारा इसका एक उदाहरण बनकर उभरा है। बालोद जिले के जनपद पंचायत डौंडीलोहारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देव ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 7.60 लाख रुपये की लागत से एक ईवी गार्बेज रिक्शा और एक ईवी लोडर वाहन उपलब्ध कराया गया है। ईवी गार्बेज रिक्शा के माध्यम से स्व-सहायता समूह की महिलाएं घर-घर पहुंचकर गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण कर रही हैं, जिससे गांवों में स्वच्छता व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हुई है।

गांव-गांव में मनाया गया रोजगार एवं आवास दिवस

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विकसित भारत जी-राम-जी योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। रोजगार एवं आवास दिवस के दौरान श्रमिकों को बताया गया कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना के अंतर्गत अब पात्र ग्रामीण श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। समीक्षा तथा हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से बदली हड़मे कवासी की जिंदगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम जैमेर की रहने वाली हड़मे कवासी की जिंदगी कभी कठिनाईयों से भरी थी। आत्मसमर्पित नक्सली स्वर्गीय कवासी सोमडू देवा के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई।

वे एक जर्जर कच्ची झोपड़ी में रहती थीं, जहां बरसात में पानी टपकता था और गर्मी के दिनों में रहना भी मुश्किल हो जाता था। सीमित संसाधनों के कारण परिवार का जीवन संघर्षों में बीत रहा था। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आईं। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का मकान स्वीकृत हुआ। आज उनका सुंदर, सुरक्षित और पक्का घर बनकर तैयार है। अब उनका परिवार हर मौसम में सुरक्षित और सम्मान के साथ रह रहा है। घर के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय का निर्माण भी कराया गया। इससे परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिला तथा उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।

आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बढ़ रही आगे: हड़मे कवासी का जीवन केवल पक्के घर तक ही नहीं बदला, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी मजबूत बनीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत वे रैला पुंगार स्व- सहायता समूह से जुड़ीं। समूह के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों में भाग लेकर वे नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर रही हैं।

जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही हैं हड़मे कवासी: हड़मे कवासी बताती हैं कि पहले उनका जीवन अभावों और असुरक्षा से भरा था, लेकिन आज उनके पास पक्का घर, शौचालय और नियमित आय का साधन है। वे इसके लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। हड़मे कवासी की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि शासन की योजनाएं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचकर उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही हैं।

जीपीएम का 'विष्णुभोग' चावल बना महिलाओं की समृद्धि का नया ब्रांड

बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के जैविक उत्पाद को जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का भरपूर समर्थन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) का प्रयास लगातार सफल हो रहा है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जैविक पद्धति से उत्पादित और प्रसंस्कृत अरपा-बिहान विष्णुभोग चावल को अब जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

इसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित असेंबली हॉल में आयोजित स्थानीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महज 30 मिनट में 45 हजार रुपये से अधिक मूल्य के विष्णुभोग चावल की बिक्री हुई।

यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, गुणवत्ता आधारित उत्पादन और राज्य सरकार की आजीविका उन्मुख योजनाओं पर बढ़ते जनविश्वास का प्रमाण है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से सीधे चावल खरीदकर

उनके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची तथा कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्वयं विष्णुभोग चावल खरीदकर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वहीं स्थानीय निवासी पंकज तिवारी ने एक साथ 200 किलोग्राम विष्णुभोग चावल खरीदकर अब तक के सबसे बड़े खरीदार बनने का गौरव प्राप्त किया। उनके इस कदम ने अन्य नागरिकों को भी स्थानीय उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीओ) इस पहल की प्रमुख कड़ी बनकर उभरी है। महिलाओं द्वारा जैविक पद्धति से उत्पादित विष्णुभोग धान का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण, आकर्षक ब्रांडिंग, गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग और व्यवस्थित विपणन किया जा रहा है। इससे उत्पाद को बेहतर बाजार मिलने के साथ-साथ किसानों और महिला उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है।

जिले में इस पहल को आगे बढ़ाने में कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुकेश रावटे की सक्रिय भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। उनके मार्गदर्शन में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और सार्वजनिक मंचों पर लगातार विष्णुभोग चावल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है और अधिक महिलाएं इस मॉडल से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि जिले में मिशन के अंतर्गत 179 सीएमएसए (कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विष्णुभोग धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो और स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लखपति दीदी अभियान के तहत आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों पर नगर पंचायत बारसूर सख्त

सितंबर से पहले निर्माण पूरा करने के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (1.0) के तहत दंतेवाड़ा जिले की नगर पंचायत बारसूर ने वर्षों से अधूरे पड़े आवासों को पूरा कराने के लिए अभियान शुरू किया है। नगर पंचायत ने ऐसे 51 हितग्राहियों की पहचान की है, जिनके मकानों का निर्माण निर्धारित समय के बाद भी पूरा नहीं हुआ है।

नगर पंचायत की टीम सभी अधूरे आवासों का मौके पर जाकर निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के बाद संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें सितंबर 2026 से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत के अनुसार, कई हितग्राहियों को योजना की विभिन्न किश्तों की राशि मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पूरा नहीं किया। जिन हितग्राहियों को फाउंडेशन स्तर की राशि मिली थी, उन्हें लिंटल स्तर तक निर्माण करना था। छत स्तर की राशि प्राप्त करने वालों को रूफ स्तर तक तथा रूफ स्तर की राशि पाने वाले हितग्राहियों को फिनिशिंग तक निर्माण कार्य पूरा करना था। इसके बावजूद कई मकान अब भी अधूरे हैं। मुख्य

नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (1.0) के सभी अधूरे आवासों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। नगर पंचायत की टीम हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें जल्द निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है। नगर पंचायत बारसूर द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान योजना के अधूरे आवासों को जल्द पूरा कर पात्र हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अल-नीनो की आशंका पर कृषि विभाग अलर्ट

किसानों को फसल विविधीकरण और जल संरक्षण अपनाने की सलाह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अल-नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि मानसून में देरी, लंबे अंतराल तक सूखे जैसी खंड वर्षा तथा बारिश का मौसम समय से पहले समाप्त होने की आशंका के कारण खरीफ फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए राज्य में विशेष आकस्मिक कार्ययोजना लागू की है।

कृषि विभाग के अनुसार कार्ययोजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से सीमित संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करना है। किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली तथा कम पानी की आवश्यकता वाली धान की उन्नत किस्मों के चयन की सलाह दी गई है।

कृषि विभाग के अनुसार टिकरा और भर्री जैसी ऊंची एवं ढलान वाली भूमि में समय पर बुआई और नमी संरक्षण के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) पद्धति अपनाना लाभकारी रहेगा। किसानों से केवल धान पर निर्भर रहने के बजाय फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की गई है। अरहर, मूंग, उड़द जैसी दलहनी तथा

तिल, सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग (भूमि आच्छादन) तकनीक अपनाने, मेड़बंदी को मजबूत करने तथा वर्षा जल संरक्षण के स्थानीय और पारंपरिक उपायों को पुनर्जीवित करने की भी सलाह दी गई है। इससे वाष्पीकरण कम होगा और उपलब्ध नमी का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

कृषि विभाग ने किसानों से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है। खेती के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या मौसम संबंधी कठिनाई आने पर निकटतम कृषि विभाग के अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन लेने को कहा गया है।

जैव विविधता पार्क कांकेर के माकड़ी में औषधिय पौधों का रोपण, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की नई पहल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बचाने और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया है। जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन के विशेष अवसर पर कांकेर के माकड़ी जैव विविधता पार्क में एक भव्य औषधीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं, बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अजय शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे. ए. सी. एस. राव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इन सभी पदाधिकारियों ने पार्क में औषधीय पौधों का रोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बोर्ड के अध्यक्ष

विकास मरकाम ने उपस्थित सभी लोगों को हमारे पारंपरिक ज्ञान और औषधीय पौधों को सहेजने व उनकी सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया। उपाध्यक्ष औषधि पादप बोर्ड श्री अजय शुक्ला ने कहा कि ?यह आयोजन वन और जन के बीच की दूरी को कम करने वाला है। यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा।

लगाए गए स्वास्थ्य के लिए जीवनदायी पौधे

पार्क की जैव-विविधता और औषधीय संपदा को समृद्ध करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पौधे रोपे गए। इनमें मुख्य रूप से त्रिफला के घटकों के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी निम्नलिखित प्रजातियां शामिल हैं जिसमें आँवला, विटामिन-सी से भरपूर और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ाने में मददगार। जामुन मधुमेह (डायबिटीज) को नियंत्रित करने और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए उपयोगी। अर्जुन की छाल को हृदय रोगों के उपचार के लिए अचूक औषधि माना जाता है। ?हर्रा पाचन तंत्र को सुधारने और पेट के विकारों को दूर करने में सहायक। ?बहेड़ा श्वसन तंत्र की मजबूती और कफ से जुड़े रोगों के निवारण के लिए फायदेमंद। ?नीम प्राकृतिक एंटी-सेप्टिक और रक्त को शुद्ध करने वाला गुणकारी पौधा है। इस सफल कार्यक्रम में कांकेर जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आए पारंपरिक वैद्यों, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान कांकेर के वनमंडलाधिकारी रौनक गोयल, उप वनमंडलाधिकारी कांकेर, उप वनमंडलाधिकारी कोरर सहित वन विभाग का पूरा अमला उपस्थित रहा।

विजयपुर में 16 करोड़ रुपये से बनेगा अत्याधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डिजाइन में सुधार कर शीघ्र स्वीकृति भेजने के निर्देश

रायगढ़ में स्वास्थ्य, पर्यटन और शहरी अधोसंरचना विकास को मिलेगी नई रफ्तार : ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजयपुर में प्रस्तावित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, केलो नदी के खर्रा घाट पर विकसित किए जा रहे मैरीन ड्राइव तथा पुराने जेल परिसर में प्रस्तावित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

विजयपुर में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को भवन की ड्राइंग एवं डिजाइन में आवश्यक सुधार कर इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक उपयोगी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्र अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाए, ताकि निर्माण कार्य जल्द

प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से रायगढ़ जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इसके बाद वित्त मंत्री ने केलो नदी के खर्रा घाट पर लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे मैरीन ड्राइव परियोजना का निरीक्षण किया। लगभग दो किलोमीटर लंबी इस परियोजना का कार्यादेश जारी हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह परियोजना रायगढ़ की नई पहचान बनेगी, इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मैरीन ड्राइव परियोजना के अंतर्गत घाट का सौंदर्यीकरण, गज़ीबो, आरसीसी पाथवे, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, प्रोमेनेड, फूड कोर्ट, बाह्य विद्युतीकरण सहित विभिन्न आधुनिक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके पूर्ण होने से शहरवासियों को मनोरंजन, पर्यटन और सार्वजनिक उपयोग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने पुराने जेल परिसर का भी अवलोकन किया, जहां जर्जर भवन को हटाकर आधुनिक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर महापौर श्री जीवर्धन चौहान, श्री विजय अग्रवाल, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्लैक शिमरी टॉप और डेनिम में पलक तिवारी ने ढाया कहर

सिजलिंग अदाओं से उड़ाए फैंस के होश

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। पलक अपने प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अपने लाजवाब ड्रेसिंग सेंस और बोल्ड फैशन चॉइस के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं।

इन तस्वीरों में पलक का अंदाज इतना बोल्ड और ग्लैमरस है कि फैंस उनके लुक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। पलक ने एक बॉडी-हगिंग मैटेलिक ब्लैक कलर का फुल-स्लीव टॉप पहना हुआ है, जिसमें फ्रंट-ओपन बटन डिटेलिंग है। यह शिमरी टॉप उनके लुक को एक एजी और नाइट-पार्टी वाइब दे रहा है।

इस टॉप के साथ पलक ने लो-वेस्ट, सुपर वाइड-लेग ग्रे डेनिम जींस पेयर की है, जो उनके टोंड फिगर को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रही है। यह क्लासिक ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन विजुअली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।

तस्वीरों में पलक वह अपने चेहरे पर बिखरी जुल्फों को संभालते हुए सीधे कैमरे में गहराई से देख रही हैं, जिससे उनके किलर एक्सप्रेशंस उभर कर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वह बेहद सेक्सी और कॉन्फिडेंट पोज देती नजर आ रही हैं।

अपने इस कैजुअल लेकिन हॉट लुक को कम्पलीट करने के लिए पलक ने मेकअप और एक्सेसरीज पर भी खास ध्यान दिया है। पलक ने ब्राउन टोन का न्यूड ग्लैम मेकअप चुना है। उन्होंने अपने बालों को हल्का वेवी टच देकर साइड-पार्टिंग के साथ खुला छोड़ा है।

पलक तिवारी की इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है। कमेंट सेक्शन में फैंस हार्ट और फायर इमोजीस की बरसात कर रहे हैं। कोई उन्हें गॉर्जियस कह रहा है तो कोई एब्सोल्यूट स्टनर।

पति के साथ प्रियंका चोपड़ा ने पेरिस फैशन वीक में दिखाया जलवा

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में पेरिस फैशन वीक में शामिल हुईं। यहां से उन्होंने अपने पति और बेटी के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा है।

प्रियंका चोपड़ा ने पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया है। उन्होंने इस इवेंट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। प्रियंका ने अपने पति निक जोनस के साथ जब स्टाइलिश अंदाज में एंट्री की, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रह गईं। इस स्टार कपल ने इवेंट में फ्रंट रो में बैठकर अपने बेहतरीन फैशन सेंस का जलवा दिखाया।

पेरिस में दिखे प्रियंका और निक

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है, उसमें देखा जा सकता है कि दोनों हाथ में हाथ डाले हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने ऑरेंज रंग का ड्रामेटिक लेयर्ड गाउन पहना। साथ में सन ग्लास लगाया। वहीं निक जोनस ने क्लासिक ग्रे सूट पहना। उनके जूतों ने लोगों का ध्यान खींचा है।

कैमरे के सामने दिए पोज

वेन्यू पर पहुंचने पर प्रियंका और निक ने कैमरे के सामने पोज दिए। एक अच्छे पति की तरह निक ने अपनी पत्नी की कमर पर हाथ रखा और फोटो के लिए पोज दिया। फोटो सेशन के बाद, यह कपल वेन्यू के अंदर गया और वहां अपनी फ्रंट-रो सीट पर बैठ गया। प्रियंका चोपड़ा ने जो पोस्ट शेयर की है, उसमें उन्होंने लिखा 'बेहतरीन कलेक्शन के लिए शुक्रिया निक जोनस'। प्रियंका ने इवेंट में जाने से पहले की अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इवेंट में प्रियंका अपनी बेटी मालती को भी ले गईं। उन्होंने उसकी तस्वीर भी शेयर की है।

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

प्रियंका इन दिनों एसएस राजामौली और महेश बाबू के साथ अपनी फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए पेरिस में मौजूद डायरेक्टर ने बताया कि उनकी टाइम-ट्रैवल कहानी वाली फिल्म की शूटिंग के अभी भी 80 दिन बाकी हैं।

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का पहला गाना 'जुनून' हुआ रिलीज

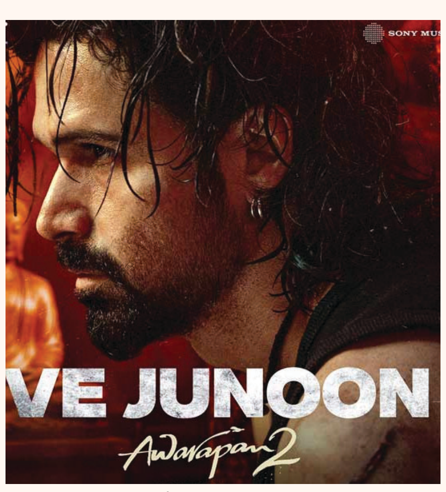

'आवारापन 2' के निर्माताओं ने इमरान हाशमी की फिल्म का पहला गाना 'जुनून' रिलीज कर दिया है। इस गाने को गायक सुबोध शर्मा ने गाया है।

विशेष फिल्म्स ने हाल ही में 'आवारापन 2' का टीजर जारी किया था। वहीं आज निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'जुनून' रिलीज कर दिया है। इस गाने के बोल शहीद कादरी ने लिखे हैं और मिथुन ने कंपोज किया है।

'आवारापन 2' का पहला गाना हुआ रिलीज

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' का पहला गाया 'जुनून' रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में इमरान हाशमी से लेकर दिशा पाटनी और श्रेया सरन की खास झलक देखने को मिली। इमरान ने इंस्टाग्राम पर अपने इस गाने को साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'इस आवारापन के जुनून में होना है तबाह।'

यूजर्स के कमेंट्स

यूट्यूब पर इस गाने को एक घंटे के अंदर अभी तक 136 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। इस गाने को लेकर यूजर्स अपनी राय पेश कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'इस गाने की रचना थोड़ी 'सैयारा' से मिलती जुलती लग रहा है'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'श्रेया सरन के पुराने सींस को देखकर अच्छा लगा।'

एक और यूजर ने लिखा, 'आवारापन के गानों की बात ही अलग थी'

एक यूजर ने इमरान के लिए लिखा, 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ'

एक और यूजर ने लिखा, 'शिवम वापस आ गया है' एक और यूजर ने लिखा, 'इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता, पहले दिन ही हिट हो जाएगी'

कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'

फिल्म 'आवारापन 2', 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और दिशा पटानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में श्रेया सरन का भी अहम रोल है।

क्या खूंखार विलेन बनेंगी तब्बू? 28 वर्षों बाद नागार्जुन की किंग 100 में आएंगी नजर

तब्बू साउथ की फिल्म में एक खास रोल निभाने जा रही हैं। वह नागार्जुन की फिल्म 'किंग 100' में नजर आएंगी। यह जोड़ी 28 वर्षों के बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करेगी। साउथ के अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म की जब से घोषणा हुई है, तभी से लोगों में इसे लेकर उत्सुकता है। इसका नाम अभी के लिए 'किंग 100' रखा गया है। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी।

क्या होगा तब्बू का किरदार?

यह पहले से पता था कि फिल्म में तब्बू नागार्जुन के साथ रोमांटिक रोल में नहीं होंगी, मगर उनके किरदार के बारे में जानकारी गुप्त रखी गई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तब्बू फिल्म में विलेन (खलनायक) का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।

किन फिल्मों में निभाए सख्त रोल?

वैरायटी इंडिया के मुताबिक तब्बू 'किंग 100' में विलेन का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म के जरिए वह 28 साल बाद नागार्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इसके निर्देशक आर.ए. कार्तिक हैं। तब्बू ने फिल्म 'मकबूल', 'हैदर', 'अंधाधुन' और 'फितूर' जैसी फिल्मों में अलग तरह के किरदार निभाकर तारीफें बटोरी हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

तब्बू को आखिरी बार अक्षय कुमार, वामिका गब्बी और परेश रावल के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में देखा गया था। उन्होंने हाल ही में एचबीओ की 'ड्यून: प्रोफेसी' में सिस्टर फ्रांसेस्का की अहम भूमिका निभाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है।

कब साथ नजर आई थी जोड़ी?

तब्बू और नागार्जुन आखिरी बार 1998 की तेलुगु फिल्म 'आविडा मा आविडे' में साथ नजर आए थे। उससे पहले 1996 की हिट फिल्म 'निन्ने पेल्लाडाटा' में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में, उनका यह नया सहयोग फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा करने वाला पल है। तब्बू ने अप्रैल में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी।

आंखों की थकान का कारण बन सकती है ज्यादा स्क्रीन टाइम, जानिए इसके लक्षण

आज के समय में स्क्रीन टाइम का बढ़ता उपयोग आंखों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। चाहे वह कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या टीवी, अधिक समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की थकान हो सकती है। यह लेख आपको कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएगा, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी आंखें थकी हुई हैं और आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए।

आंखों की जलन और खुजली होना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय आंखों में जलन या खुजली महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में तुरंत आंखों को आराम दें और उन्हें ठंडे पानी से धोएं या आंखों की बूंदों का उपयोग करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी, जिससे आपकी आंखों की थकान कम होगी।

सिरदर्द होना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय सिरदर्द होता है तो यह भी एक सामान्य समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें और सिर एक-दूसरे पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जिससे दर्द होता है। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे सिरदर्द कम होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे।

आंखों का धुंधला दिखना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय चीजें धुंधली दिखती हैं तो यह भी आंखों की थकान का संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे आपकी आंखों की संवेदनशीलता कम होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।

लगातार झपकना

अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आंखें बार-बार झपक रही हैं तो यह भी एक सामान्य संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी।

आंखों का सूखना

अगर आप पाते हैं कि आपकी आंखें सूखी हो रही हैं तो यह भी आंखों की थकान का एक संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। इस स्थिति में आंखों की बूंदों का उपयोग करें ताकि आपकी आंखें नमी बनी रहें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी आंखों की थकान को कम कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।

सड़क नहीं, समृद्धि का नया मार्ग: NH-130D ने बदली नारायणपुर की सूरत और सीरत

किसान, छात्र और मरीजों के लिए सुगम हुआ सफर, विकास को मिले नए पंख

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर की संरचना नहीं होतीं, बल्कि वे किसी भी अंचल के भाग्य और विकास की जीवनरेखा होती हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में विकास की एक ऐसी ही नई इबारत राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी के रूप में लिखी गई है। इस हाईवे के कोण्डागांव-नारायणपुर मार्ग पर 12.6 किलोमीटर लंबे खंड किलोमीटर 32.200 से 44.800 तक के उन्नयन और मजबूतीकरण ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। यह परियोजना अब केवल एक सड़क निर्माण कार्य न रहकर, बस्तर संभाग के इस महत्वपूर्ण अंचल में सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मजबूत आधार बन चुकी है।

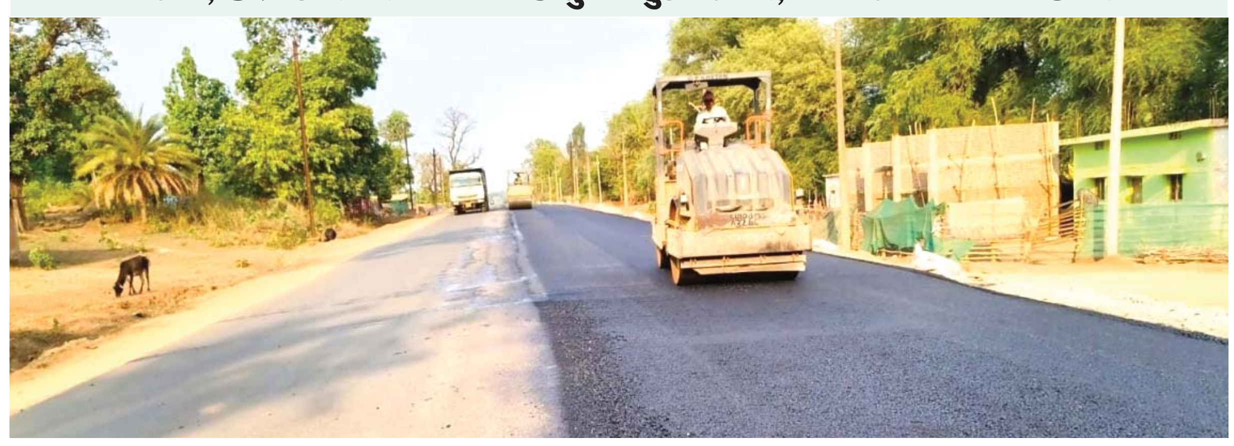

कुछ समय पहले तक इस मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। गड्ढों से भरी इस सड़क पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं था। महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। मानसून के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। वाहन चालकों के सिर पर हमेशा दुर्घटना का साया मंडराता रहता था। खराब कनेक्टिविटी के कारण गंभीर मरीजों को समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना और किसानों के लिए अपनी उपज मंडियों तक ले जाना एक दु:स्वप्न जैसा था।

कम हुआ समय, सुरक्षित हुआ सफर

NH-130D के इस महत्वपूर्ण खंड के कायाकल्प के बाद आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से न सिर्फ यात्रा का समय आधा रह गया है, बल्कि सफर बेहद सुरक्षित और आरामदायक हो गया है। सड़क की समतल और उच्च गुणवत्ता वाली सतह ने हादसों की आशंका को न्यूनतम कर दिया है, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, थमी परिवहन लागत

इस सुगम सड़क का सबसे सीधा और बड़ा असर क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। अन्नदाताओं को अब अपनी कृषि उपज प्रमुख बाजारों और सोसायटियों तक पहुंचाने में आसानी हो रही है, जिससे उनके समय और परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भारी बचत हो रही है। छोटे व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए सामान की लोडिंग-अनलोडिंग और आवागमन सरल व किफायती हो गया है। बेहतर सड़क होने के कारण वाहनों में ईंधन की खपत कम हुई है और उनके रखरखाव (मेंटेनेंस) का खर्च भी घटा है, जिससे कमर्शियल वाहन मालिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस सड़क ने नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को भी संजीवनी का काम किया है। अब आपातकालीन स्थिति में गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस के माध्यम से बिना किसी व्यवधान के जिला अस्पताल या अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों तक बेहद कम समय में पहुंचाया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर अंचल के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थानों तक का सफर अब सुरक्षित हो गया है, जिससे ड्रॉप-आउट दरों में कमी आएगी और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

प्रशासन के प्रति बढ़ा जन-विश्वास

सड़क के इस कायाकल्प से नारायणपुर और कोण्डागांव के स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह है। नियमित सफर करने वाले राहगीरों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर काम पूरा होने से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है।

NH-130D का यह नया स्वरूप महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नारायणपुर के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का नया प्रवेश द्वार है, जो आने वाले समय में रोजगार, व्यापार और उन्नत जीवन स्तर की नई संभावनाओं को गढ़ता रहेगा।

खास खबर

स्व-सहायता समूह से जुड़कर सुशीला सिंह बनीं आत्मनिर्भर

रायपुर। राज्य शासन की महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि स्वरोजगार अपनाकर समाज में अपनी अलग पहचान भी बना रही हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के ग्राम छतरंग की सुशीला सिंह की कहानी महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरी है। कभी कृषि मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाली श्रीमती सुशीला सिंह आज बीसी सखी के रूप में कार्य करते हुए डिजिटल सेवा केंद्र संचालित कर रही हैं। स्व-सहायता समूह से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियां उन्हीं पर थीं। सीमित आय के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान उन्हें स्व-सहायता समूह की जानकारी मिली और उन्होंने समूह की सदस्यता ग्रहण की।

जशपुर में मत्स्य बीज उत्पादन शुरू, किसानों को अनुदान पर मिल रहा मत्स्य बीज

रायपुर। जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फ्राई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत नि:शुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी। शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फ्राई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

वैज्ञानिक पशुपालन से आत्मनिर्भरता की राह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में वैज्ञानिक पशुपालन अब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में पशुधन विकास विभाग द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसके तहत महासमुंद जिले के विकासखण्ड बागबाहरा के ग्राम जोरातराई की महिला पशुपालक समूह को धमतरी जिले के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया। यहाँ महिलाओं ने मुख्य ग्राम योजना भोथली के अंतर्गत ग्राम बोड़रा स्थित गौधाम और गोविन्दी देव गौशाला का दौरा कर आधुनिक डेयरी प्रबंधन और उन्नत तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी हासिल की। कैसे पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैज्ञानिक पशुपालन को अपनाकर अपनी आय को दोगुना किया जा सकता है।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तता की नई पहचान बना जीपीएम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल लगातार प्रभावी परिणाम दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी अभियान में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्य का 90 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में जिले की बड़ी सफलता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को 10 हजार 124 लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य मिला था। इसके विरुद्ध अब तक 9 हजार 95 महिलाएं लखपति दीदी बनने का लक्ष्य हासिल कर चुकी हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति, बिहान मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिला प्रशासन के सतत मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प है कि प्रदेश की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित न रहें, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनकर अपने परिवार, समाज और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य सरकार स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।

जिले में वर्तमान में 6 हजार 10 स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं। इन समूहों को औसतन 1 लाख 92 हजार रुपये प्रति समूह का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, लघु उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को नई गति मिली है। इससे हजारों ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के समन्वित प्रयासों से महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि उद्यमिता विकास, कौशल प्रशिक्षण, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव तथा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि जिले की बड़ी संख्या में महिलाएं आज सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। लखपति दीदी अभियान ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान ने न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास किया है।

मुख्यमंत्री साय से झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की सौजन्य भेंट

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड केवल भौगोलिक रूप से पड़ोसी राज्य ही नहीं हैं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों की मजबूत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जशपुर क्षेत्र का झारखंड से वर्षों पुराना आत्मीय जुड़ाव रहा है, जिसने दोनों राज्यों के लोगों के बीच विश्वास और निकटता को निरंतर मजबूत किया है। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा परस्पर अनुभवों के आदान-प्रदान जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास के नए अवसर सृजित होंगे तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा।

वन महोत्सव के अवसर पर कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में हुआ व्यापक वृक्षारोपण

श्रीकंचनपथ समाचार

बेमेतरा। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ढोलिया (बेमेतरा) में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. अनूप कुमार सिंह ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के आधार हैं। वृक्ष न केवल हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनका संरक्षण करने का संकल्प लेना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण करना भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधे का रोपण कर उसका संरक्षण सुनिश्चित करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने वृक्षों की नियमित देखभाल करने तथा अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर डॉ. यू. के. ध्रुव, डॉ. असित कुमार, कुंती बंजारे, डॉ. भारती बघेल, डॉ. हेमलता निराला, डॉ. प्रीति पैंकरा, डॉ. साक्षी बजाज, श्रीमती प्रतिभा सिंह, डॉ. सरिता शर्मा, डॉ. महानंद, डॉ. रामेश्वर, श्री संजीव गुर्जर सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो और हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल

हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : मंत्री अग्रवाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (अंग्रेजी माध्यम), ब्रम्हरोड अंबिकापुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में सहभागिता करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ नए शैक्षणिक सत्र का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा शिक्षा को जीवन में सफलता का सबसे प्रभावी माध्यम बताया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने और बेटियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

छात्राओं को साइकिल वितरण केवल एक योजना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे बेटियों की विद्यालय तक सुरक्षित और सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी तथा वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगी।

उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय ज्ञान, संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यार्थी पूरे मनोयोग से अध्ययन करें, अनुशासन और मेहनत को अपना जीवन मंत्र बनाएं तथा अपने माता-पिता, शिक्षकों और प्रदेश का नाम रोशन करें। आज का परिश्रम ही कल की सफलता का आधार बनेगा।

मंत्री अग्रवाल ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक नवाचार कर रही है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के माध्यम से प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा, संस्कार और प्रतिभा के बल पर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2026 के लिए 27 तक नामांकन

धमतरी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं एवं पात्र संगठन निर्धारित अवधि के भीतर अपना नामांकन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी जिला समाज कल्याण विभाग, धमतरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 1 जून 2026 से 27 जुलाई 2026 तक संचालित की जा रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि नामांकन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।

खास खबर

प्रतिबंधित टेबलेट की डिलीवरी देने निकले तीन आरोपी हुए गिरफ्तार

भिलाई। क्राइम ब्रांच और सुपेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित अल्प्राजोलम टैबलेट की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 840 अल्प्राजोलम टैबलेट, तीन मोबाइल फोन और 1,600 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी मोहन नगर क्षेत्र से प्रतिबंधित टैबलेट लेकर जामुल इलाके में सप्लाई देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग टीमें गठित कीं। एक टीम ने मोहन नगर से आरोपियों का पीछा शुरू किया, दूसरी जामुल क्षेत्र में निगरानी के लिए तैनात रही, जबकि तीसरी टीम नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर इंतजार करती रही। सोमवार सुबह करीब 10 बजे नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास एक आरोपी को पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन खान उर्फ अमन रक्सेल, अमर साहू और पंकज उर्फ भक्का विश्वकर्मा के रूप में हुई है। तीनों मोहन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

चंगोराभाठा में लूटपाट करने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर के चंगोराभाठा इलाके में राह चलते युवक से मारपीट कर चांदी की चेन और मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाशों को डी.डी. नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंची पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक, 5 जुलाई की शाम चंगोराभाठा बाजार स्थित बाबा चौक के पास स्कूटी सवार दो युवकों ने एक युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने उसके गले से चांदी की चेन और जेब में रखा मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर 7 जुलाई को डी.डी. नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत मामला दर्ज किया गया इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने रजत सेन उर्फ हर्ष (19) और लक्की ध्रुव (19), दोनों निवासी मटकोड़वापारा, चंगोराभाठा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

खंभे से बांधकर पीटने से ग्रामीण की मौत, मिली आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ग्रामीण को बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल, 22 दिसंबर 2024 को अर्जुन सारथी ने चक्रधर नगर थाने में सूचना दी कि 21 दिसंबर की रात वह परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। अगली सुबह करीब 5:30 बजे वह बनौरा आश्रम के पास टहल रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संतोष सिदार से हुई। उसने बताया कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) को डूमरपाली गांव के बाहर बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से पीटा गया है। सूचना मिलने पर अर्जुन सुबह करीब 6 बजे डूमरपाली पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता बिजली के खंभे के पास पड़े थे। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और उनकी मौत हो चुकी थी।

म्यूल अकाउंट मामले में दुर्ग पुलिस की कार्रवाई अलग-अलग प्रकरण में 10 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने, छिपाने, स्थानांतरित करने एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर 8 खाताधारकों को गिरफ्तार कर विभिन्न मोबाइल, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड एवं आधार कार्ड जब्त किए। इसी प्रकार छावनी पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार 15 आरोपियों के अतिरिक्त गिरोह के 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार दो अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों का परीक्षण किया गया। जांच में यह पाया गया कि विभिन्न बैंक खातों में साइबर ठगी से प्राप्त राशि प्राप्त होकर अन्य खातों में स्थानांतरित की गई, जिससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि संबंधित खाताधारकों द्वारा स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम को प्राप्त करने, छिपाने एवं स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया गया। उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3), 318(4) बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर दोनों थानों में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक के संदिग्ध खातों की जांच के दौरान 106 खाताधारकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें विवेचना के दौरान 08 खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड एवं आधार कार्ड जप्त किए गए। इसी प्रकार थाना छावनी में पंजीबद्ध प्रकरण में पूर्व में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। विवेचना के दौरान दो अन्य आरोपी प्रेमलाल कौशिक एवं ललित कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश एवं विवेचना जारी है।

उक्त कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली एवं थाना छावनी की पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विवेचना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास जारी हैं। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल नंबर अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी उपयोग हेतु उपलब्ध न कराएं। कमीशन अथवा प्रलोभन के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराना भी दंडनीय अपराध है। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

आरोपियों के नाम

मोदित कुमार जैन, उम्र 26 वर्ष, निवासी नूतन चौक, भिलाई-3।

करण टण्डन, उम्र 21 वर्ष, निवासी पांच रास्ता, सुपेला, भिलाई।

अवध किशोर, उम्र 55 वर्ष, निवासी सेक्टर एच, खुर्सीपार, भिलाई।

संकेत कुमार दास, उम्र 27 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, भिलाई।

रविन्द्र कौशिक, उम्र 20 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर, खुर्सीपार।

शहबाज आलम, उम्र 26 वर्ष, निवासी जवाहर नगर, जामुल।

ए. सागर, उम्र 36 वर्ष, निवासी वृंदा नगर, सुपेला।

प्रिती कौर, उम्र 37 वर्ष, निवासी गांधी कॉलोनी, सुपेला।

प्रेमलाल कौशिक, उम्र 23 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, भिलाई।

ललित कुमार, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, भिलाई।

अपहरण व लूटपाट की वारदात का खुलासा चार नाबालिग सहित 6 आरोपी हुए गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। अपहरण कर लूटपाट की वारदात में शामिल 6 आरोपियों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें चार नाबालिग भी शामिल है। इन सभी ने मिलकर गदा चौक के पास एक व्यक्ति से मारपीट कर नकदी, मोबाइल, स्कूटी, चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान लूट लिया था। आरोपियों द्वारा प्रार्थी के डिजिटल भुगतान माध्यम से जबरन राशि ट्रांसफर कराकर कुल 87,180 की लूटपाट की गई थी। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रार्थी शिक्षक कॉलोनी, डौंडी, जिला बालोद निवासी द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 2 जुलाई 2026 की रात्रि वह अपने रिश्तेदार के साथ दुर्ग-भिलाई घूमने आया था। प्रात: लगभग 4:30 बजे गदा चौक स्थित पुरानी शराब भट्ठी के पास स्कूटी खराब होने पर कुछ युवकों से सहायता मांगी। बातचीत के दौरान आरोपियों ने स्कूटी चोरी की होने का संदेह जताते हुए अपने अन्य साथियों को बुलाया तथा प्रार्थी एवं उसके साथी का जबरन अपहरण कर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर मारपीट की।

आरोपियों द्वारा प्रार्थी से चांदी की अंगूठियां, चांदी का ब्रेसलेट, स्कूटी, दो मोबाइल फोन, नगदी, पर्स, आवश्यक दस्तावेज एवं इलेक्ट्रिकल कार्य का सामान छीन लिया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को धमकाकर उसके डिजिटल भुगतान माध्यम से 18,180 की राशि भी जबरन ट्रांसफर कराई गई। बाद में पुलगांव क्षेत्र में ले जाकर धारदार हथियार दिखाकर धमकी दी गई तथा जबरन वीडियो बनवाकर शिकायत नहीं करने के लिए भयभीत किया गया।

प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रार्थी से पहचान कराकर 2 आरोपियों सोहेल खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी शीतला मंदिर के पास, इंद्रा नगर, सुपेला व पंकज विश्वकर्मा, उम्र 18 वर्ष, निवासी गदा चौक, सुपेला व 4 अपचारी बालकों को अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के 02 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक अम्बर भारद्वाज, सउनि अमर दास गंगेले, प्रधान आरक्षक प्रकाशचंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, आरक्षक दुर्गेश सिंह राजपूत एवं आरक्षक प्रदीप सिंह की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। कानून अपने हाथ में न लें तथा किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर कार्रवाई, महालक्ष्मी कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बेमेतरा जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रनबोड़ स्थित मेसर्स महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण, विक्रय या उर्वरक व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेगा।

कृषि विभाग के अनुसार संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्सन, अधिक कीमत पर बिक्री तथा नकली और अमानक उर्वरकों की रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जून को नवागढ़ विकासखंड के रनबोड़ स्थित महालक्ष्मी कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के कई प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।

जांच के दौरान कैश मेमो पर किसानों के हस्ताक्षर नहीं मिले। भंडारण एवं विक्रय पंजी का संधारण अपूर्ण पाया गया, निर्धारित प्रारूप में मासिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा बिक्री स्थल पर उर्वरकों का स्टॉक और निर्धारित विक्रय दर भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में अन्य जिलों के किसानों को उर्वरक बेचे गए। इसके अलावा पीओएस सिस्टम में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में भी अंतर पाया गया।

इन अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन विभाग को दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं सह प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ की अनुशंसा पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूने मकान से जेवरात उड़ाने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार, 3 लाख का ज्वेलरी बरामद

रायपुर। रायपुर के आजाद चौक थाना इलाके में सूने मकान से सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने वाले एक युवक और नाबालिग को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी का नाम मोहम्मद बिलाल (19) बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के करीब 3 लाख रुपए कीमत के सभी जेवरात बरामद कर लिए हैं। एक आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, हांडीपारा निवासी कांति साहू 5 जुलाई को अपने घर में ताला लगाकर ग्राम नकटी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। अगले दिन सुबह घर लौटने पर मुख्य दरवाजे और अलमारी के लॉकर का ताला टूटा मिला।

घर का सामान बिखरा पड़ा था और लॉकर में रखे सोने-चांदी के जेवरात गायब थे। शिकायत के बाद आजाद चौक थाने में बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत केस दर्ज किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आजाद चौक थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई।

टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मुखबिरों को सक्रिय किया और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। जांच के दौरान पुलिस ने हांडीपारा निवासी मोहम्मद बिलाल (19) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को भी पकड़ लिया। दोनों की निशानदेही पर चोरी के सभी जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस के अनुसार, नाबालिग के खिलाफ पहले भी आजाद चौक थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। दोनों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

फर्जी सिम बेचने वाले 2 पीओएफ एजेंट गिरफ्तार

यूट्यूब पर वीडियो वायरल करने और केबीसी इनाम के नाम पर हुई ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले दो (पॉइंट ऑफ सेल) एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उमेश प्रजापति (23) निवासी छतरपुर, मध्यप्रदेश और मनोज देवांगन (29) निवासी खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है।

दोनों मोबाइल दुकानों का संचालन करते थे और फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए सिम साइबर अपराधियों को बेचते थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया कि आरोपियों के बेचे गए सिम कार्डों का इस्तेमाल यूट्यूब पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और 'कौन बनेगा करोड़पति' में इनाम जीतने का झांसा देकर साइबर ठगी करने जैसे मामलों में किया गया।

पुलिस के मुताबिक, गरियाबंद के इंदागांव थाना क्षेत्र में एक पीड़ित से फेसबुक पर दोस्ती कर वीडियो कॉल के जरिए उसकी वीडियो मॉर्फिंग की गई और उसे वायरल करने की धमकी देकर 7.90 लाख रुपए की ठगी की गई।

वहीं, दूसरे मामले में केबीसी में इनाम जीतने का झांसा देकर टैक्स के नाम पर रकम ऐंठी गई। दोनों मामलों की जांच रायपुर रेंज साइबर थाना कर रही थी।

आरोपी इस तरह से जारी करते थे डबल सिम

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि, नया सिम लेने या सिम पोर्ट कराने आने वाले ग्राहकों की डबल थंब स्कैन, आई ब्लिंक और ई-केवाईसी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर लेते थे।

जिन ग्राहकों के आधार की फिजिकल कॉपी होती थी, उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डी-केवाईसी के जरिए भी फर्जी सिम जारी किए जाते थे। बाद में इन सिम कार्डों को अधिक कीमत पर साइबर ठगों को बेच दिया जाता था।

अंजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि, सोशल मीडिया पर अंजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अज्ञात वीडियो कॉल से बचें और केबीसी, लॉटरी या इनाम के नाम पर टैक्स या प्रोसेसिंग फीस मांगने वाले किसी भी संदेश पर भरोसा न करें। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 30.06.2026

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)

(प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र ''अ'' में प्रतिशत दर पर दिनांक 20.07.2026 तक आमंत्रित की जाती है :-

निविदा आमंत्रण सू.क्र./सि.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
230/194745	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्ल्यू. का कार्य (जोनल एजेंसी)	25.00
231/194746	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न गैर आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्ल्यू. का कार्य (जोनल एजेंसी)	25.00
232/194747	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं रंगरोगन का कार्य (जोनल एजेंसी)	24.23
233/194749	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न भवनों में रंगाई पोताई एवं रंगरोगन का कार्य (जोनल एजेंसी)	29.87
234/194750	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं रंगरोगन का कार्य (जोनल एजेंसी)	17.61
235/194751	लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न भवनों में रंगाई पोताई एवं रंगरोगन का कार्य (जोनल एजेंसी)	35.64
236/194752	कवर्धा जिला कबीरधाम के आई.टी.आई. मुख्य मार्ग भवन के शेष निर्माण कार्य	50.31
237/194753	लोक निर्माण विभाग संभाग कवर्धा के अंतर्गत विभिन्न सड़कों एवं पुल-पुलियों में साधारण मरम्मत कार्य	24.99
238/194754	लोक निर्माण विभाग संभाग कवर्धा के अंतर्गत सड़क मरम्मत, पुल-पुलिया मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य	50.00
239/194829	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का विशेष मरम्मत कार्य (जोनल एजेंसी)	80.00
240/194830	उदस प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान एवं छात्रावास/ आश्रम के अनुरक्षण (मरम्मत) एवं विस्तार कार्य	12.42

टीप:-
1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है.
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें.

G- 262701942/9

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग

बेमता मोड़ पर तीन लोगों ने की ग्रामीण से मारपीट

तिल्दा-नेवरा। थाना तिल्दा-नेवरा क्षेत्र के ग्राम बेमता मोड़ के पास एक व्यक्ति के साथ तीन अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा में भर्ती कराया। 3 जुलाई की रात डायल-112 वाहन चालक विजय कोसले और आरक्षक शैलेन्द्र डहरिया रात्रि गश्त पर थे। तब यह सूचना मिली। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर करीब 50 वर्षीय व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं तथा वह लहूलुहान था। तत्काल 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है।

राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रशासन में आया सकारात्मक बदलाव : मुख्यमंत्री साय

बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका एवं भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की होगी व्यवस्था

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों, तकनीक आधारित नवाचारों तथा नागरिकों एवं किसानों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नागरिकों को बिना अनावश्यक कार्यालयीन आवागमन के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में डिजिटल किसान किताब एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील अथवा पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन एवं किसानों के जीवन से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के सभी सुधारों एवं नवाचारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 की ऑनलाइन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके लागू होने पर आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध होगी। उन्होंने अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष बल देते हुए सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की जिला-वार नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में **VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives)** परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूर्णतः ऑनलाइन करने के लिए इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाएगा। इससे प्रमाणित अभिलेखों का निर्गमन कुछ ही मिनटों में संभव होगा तथा अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने असर्वेक्षित ग्रामों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्व अभिलेख तैयार हो सकें, भूमि अभिलेख अद्यतन हों तथा स्थानीय नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि एवं नामांतरण, पट्टाधृति अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री एवं एक्सेम्प्टेड कैटेगरी फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन के डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी, जवाबदेह एवं विश्वासपूर्ण राजस्व व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रशासन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और इसे और अधिक प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं केंद्रीकृत एवं पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर नागरिक हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए। बैठक में ई-कोर्ट प्रणाली, रेवेन्यू बोर्ड एवं संभागीय आयुक्त कार्यालयों में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन तथा भू-अर्जन से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में नक्शा परियोजना का पायलट कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, विशेष सचिव इफ्फत आरा, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार, संयुक्त सचिव श्री अरविन्द एक्का सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोण्डागांव में नि:शुल्क पौधा वितरण केंद्र शुभारंभ

वन विभाग की पहल, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी का आह्वान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और जिले में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से वनमंडल कोण्डागांव ने मंगलवार को जगदलपुर नाका चौक में नि:शुल्क पौधा वितरण केंद्र का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है।

कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का नि:शुल्क वितरण किया तथा सभी से अपने घर, आंगन, खेत, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की।

सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वृक्ष हमें स्वच्छ हवा देने के साथ जल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण तभी सफल माना जाएगा, जब लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण भी किया जाए। उन्होंने प्रत्येक परिवार से कम से कम एक पौधा लगाने का आग्रह किया। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि हरित वातावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला है। उन्होंने नागरिकों से शासन के पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता से ही जिले को अधिक हरित और स्वच्छ बनाया जा सकता है।

वनमंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह ने बताया कि वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग जिले में पौधरोपण, नि:शुल्क पौधा वितरण और पर्यावरण जागरूकता के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

नि:शुल्क पौधा वितरण केंद्र के माध्यम से नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण अभियान से जुड़ सकें। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद कोण्डागांव के अध्यक्ष नरपति पटेल, दीपेश अरोरा, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पोस्टर का किया विमोचन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जन-जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने योजना के तहत बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले प्रदेश के 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों में 12 हजार लोगों को कुल 240 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनी है। मात्र 436 रुपए के वार्षिक अंशदान वाली यह योजना परिवारों को कठिन परिस्थितियों में संबल और भविष्य के प्रति भरोसा देने का कार्य कर रही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ अमित झिंगरन, बिजनेस स्ट्रेटजी प्रेसीडेंट संतोष चाको, वेस्ट जोन के जोनल डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव और भोपाल रीजन के रीजनल डायरेक्टर अमित कुमार साहा भी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को उपहार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवा रायपुर स्थित मुख्यालय भवन में निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, की उपस्थिति में स्टेट वेयरहाउसिंग एवं ऐक्सिस बैंक के मध्य सैलरी एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया गया। इस अवसर पर निगम के प्रबंध संचालक आशीष कुमार टिकरिहा साथ ही निगम एवं ऐक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) के तहत ऐक्सिस बैंक में निगम कर्मियों के सैलरी एकाउंट खोलने पर निगम के नियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन श्रमिकों को 1.10 करोड़ रूपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा 10 लाख का प्राकृतिक मृत्यु बीमा नि:शुल्क कवर किया जाएगा। निगम कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 8 लाख रूपये तक की शिक्षा सहायता राशि प्रदान की जायेगी। साथ ही मात्र रूपये 2499/- के वार्षिक प्रीमियम पर रूपये 30 लाख तक का हेल्थ टॉप-अप कवर एवं 30 लाख का पर्सनल ऐक्सिडेंट कवर की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने बताया की इस एम ओ यू से कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को बेहतर बैंकिंग, बीमा सुरक्षा तथा वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होगी।

इस एमओयू से निगम कर्मियों में हर्ष की लहर व्याप्त है तथा कर्मचारियों ने अध्यक्ष चंदूलाल साहू का आभार व्यक्त किया है। आज ही निगम मुख्यालय में अध्यक्ष चंदूलाल साहू द्वारा बैकुण्ठपुर (जिला-कोरिया) निवासी पूनम कूजुर को सी0सी0एच0 (चतुर्थ श्रेणी) पद पर अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक संपन्न

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाना है। संशोधन के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट सेल डिस्काउंट) से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, क्रेडिट नोट से संबंधित प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाई जाएगी।

किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, 30 जुलाई तक पूरी करें धान की रोपाई

बीज उपचार, जैव उर्वरक और लेही पद्धति अपनाने पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून अब सक्रिय हो चुका है। शुरुआती दौर में मानसून के आगमन में करीब 10 दिनों की देरी हुई, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में हुई अच्छी बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी और पानी उपलब्ध हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम खरीफफसलों, विशेषकर धान की बुआई और रोपाई के लिए अनुकूल है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम का पूरा लाभ उठाते हुए समय पर कृषि कार्य पूरा करें, ताकि उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून सामान्य समय से देर से पहुंचा, जिससे जून माह में औसत से लगभग 40 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में लगातार बारिश होने से रायगढ़ जिले सहित अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में खेतों में पर्याप्त जल उपलब्ध हो गया है। ऐसे में जहां नर्सरी तैयार है वहां मचाई कर तुरंत धान की रोपाई शुरू कर देनी चाहिए। जिन किसानों के पास नर्सरी उपलब्ध नहीं है, वे लेही पद्धति से अंकुरित बीजों की बुआई ड्रम सीडर या छिटकवा विधि से कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों ने रायगढ़ जिले के किसानों को सलाह दी है कि जो किसान धान की सीधी बुआई करते हैं, वे 15 जुलाई तक यह कार्य पूरा कर लें। वहीं रोपाई एवं बियासी पद्धति अपनाने वाले किसान 30 जुलाई तक रोपाई कर लें। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को शीघ्र एवं मध्यम अवधि (125-130 दिन) में पकने वाली धान की किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है। इनमें इन्द्रावती, छत्तीसगढ़ बारानी, इंदिरा एरोबिक, एमटीयू-1010, एमटीयू-1153, एमटीयू-1156, एमटीयू-1001, विक्रम टीसीआर, छत्तीसगढ़ धान-1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी तथा महामाया जैसी किस्में शामिल हैं, जो बदलते मौसम के अनुरूप बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं।

विशेषज्ञों ने कहा है कि धान की बुआई से पहले बीजों को कार्बेन्डाजिम अथवा अन्य उपयुक्त कवकनाशी से उपचारित करना आवश्यक है। प्रति किलोग्राम बीज में ढाई ग्राम दवा का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही एजोस्पाइरिलम, पीएसबी एवं केएसबी जैसे जैव उर्वरकों से बीज उपचार करने से फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उपलब्ध होती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है। जिन क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है और खेतों में पानी भरा हुआ है, वहां लेही पद्धति अपनाने की सलाह दी गई है। इसके लिए धान के बीजों को 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगोकर 24 से 30 घंटे तक अंकुरित किया जाए। इसके बाद मचाई किए गए खेतों में ड्रम सीडर या छिटकवा विधि से बुआई की जाए। इस पद्धति में प्रति एकड़ लगभग 40 किलोग्राम बीज का उपयोग उपयुक्त माना गया है।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि रायगढ़ जिले में धान की सीधी बुआई वाले खेतों में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में 50 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। इसलिए बुआई के बाद पहले 40 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। इसके लिए 20 एवं 40 दिन बाद हाथ से निंदाई, पैडी वीडर या आवश्यकता अनुसार अनुशंसित खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जा सकता है। उर्वरक प्रबंधन के संबंध में किसानों को सलाह दी गई है कि प्रति एकड़ अधिकतम दो बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी तथा आधी बोरी पोटाश का उपयोग करें। डीएपी और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई से पहले डालें, जबकि यूरिया की पहली खुराक 30 से 35 दिन और दूसरी खुराक 60 से 70 दिन बाद दें। इसके साथ ही हरी खाद और नील हरित काई के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। विभाग ने रायगढ़ जिले के किसानों से अपील की है कि खेती से संबंधित किसी भी समस्या या तकनीकी जानकारी के लिए निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि समय पर उचित सलाह लेकर खरीफ फसल का बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

वन विभाग में अब ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य, बिना अनुमति नहीं चलेगी फिजिकल फाइल - मंत्री केदार कश्यप

मुख्यालय से लेकर सभी फील्ड कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से होगा कामकाज, पारदर्शिता और कार्यों में आएगी तेजी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल तथा सभी फील्ड कार्यालयों में कार्यालयीन फाइलों और डाक का संचालन अब अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।

मंत्री कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा सभी कार्यों की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। इससे अनावश्यक विलंब कम होगा और आम नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है। वन विभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली अधिक तेज, प्रभावी, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनेगी। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के शत-प्रतिशत पालन की नियमित समीक्षा करें और शासन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950